women help desk स्थापित किए गए हैं। सभापति महोदय, women help desk की स्थापना से पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बन गए हैं। अब यह पुलिस स्टेशन में आने वाली महिला के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु है।

MR. CHAIRMAN: He is giving information.

श्री बंडि संजय कुमार : इससे 13,939 वूमेन हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशन में .(**व्यवधान**)....

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति जी, .(**व्यवधान**).....

श्री सभापति : आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री बंडि संजय कुमार : महोदय, law enforcement agencies, पुलिस, आईबी, एनआईए, ईडी आदि से जाँच में सहायता मिलती है।

सेक्शुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स का उपयोग यौन अपराध में साक्ष्यों को संग्रह करने के लिए किया जा रहा है। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्थापित किया गया, जिससे पुलिस, कोर्ट्स, जेल्स, फोरेंसिक लैब्स एंड प्रॉसीक्यूशन को कनेक्ट किया गया है और ये सभी विभाग आपस में डेटा शेयर करते हैं। अगस्त, 2022 से...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

1.00 **P.M.**

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The situation arising out of devastating landslide in Wayanad district in the State of Kerala

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now, we will take up the Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance. Shri Arun Singh and Dr. John Brittas to call the attention of the Minister of Home Affairs to the situation arising out of devastating landslide in Wayanad district in the State of Kerala. Shri Arun Singh.

श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं केरल राज्य के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Arun Singhji, as per practice and rules, first, you only have to draw the attention of the hon. Minister. You have drawn that attention. Hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai, to make the statement.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपसे अनुरोध किया है, उनके विचार सुनने के बाद इस संबंध में मैं बताऊंगा।

MR. CHAIRMAN: I will, now, call upon the Members to make their contributions. Shri Arun Singh may continue now.

श्री अरुण सिंह : महोदय, केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो चार गाँव हैं, वे लैंडस्लाइड के कारण पूरे तरीके से बह गए हैं। यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जो लोग मरे हैं, हम उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं, वे शीघ्र ठीक हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर, यह घटना दो बजे से लेकर छः बजे, सुबह-सुबह की घटना है और मंगलवार की घटना है। जैसे ही इस लैंडस्लाइड की घटना का पता चला, माननीय प्रधान मंत्री जी ने केरल के मुख्य मंत्री, पिनाराई विजयन जी से तुरंत बात की। उन्हें एंश्योर किया कि केंद्र से जो भी सहायता होगी, वह सहायता हम प्रदान करेंगे। जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने दो लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की है। सर, जो मारे गए हैं, उनके लिए दो लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है और जो घायल हैं, उनके लिए भी 50,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है। इसके साथ-साथ, जो एनडीआरएफ की टीम है, वह भी बचाव दल में लगी है और जो सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं, वे भी बचाव दल में लगे हुए हैं। सेना के जवान भी इस काम में लगे हुए हैं। मान्यवर, प्रधान मंत्री जी का पीएमओ कार्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और माननीय गृह मंत्री जी इस काम के लिए बचाव दल के साथ लगातार बात कर रहे हैं और प्रदेश की जो सरकार है, उससे भी लगातार बात कर रहे हैं कि जो फंसे हुए लोग हैं, उनकी जान बचाने का काम कैसे किया जाए। मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि जो यह घटना है, जो एकाएक सुबह-सुबह आई, इसके बाद तुरंत बचाव दल का काम शुरू हुआ। इसमें 400 से अधिक लोगों को बचाया गया है और अभी भी बचाने का काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी हमारी पार्टी के केरल के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे मंत्री, कुरियन जी को वहाँ भेज दिया है। हमारी पार्टी के प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष, के. सुरेंद्रन जी, वे भी इस काम में लगे हैं। उनके साथ-साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। सेवा भारती के लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेशों के पास एसडीआरएफ का पर्याप्त फंड होता है। 2005-06 से 2013-14 तक जो एसडीआरएफ का फंड था, वह 35,858

करोड़ रुपये था, वह ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए था। इसी के कंपेरिज़न में, अगर नौ साल का कार्यकाल देखेंगे, 2014-15 से 2022-23 का comparatively देखेंगे, तो माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एसडीआरएफ में तीन गुना अधिक, 1,04,704 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

एनडीआरएफ के संबंध में अगर पिछले 9 सालों में देखेंगे, तो 2005-06 से लेकर 2014-15 तक 25,036 करोड़ रुपये का ही फंड एनडीआरएफ को एलोकेट हुआ था। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस फंड के लिए 77,731 करोड़ रुपये की घोषणा हुई, मतलब तीन गुना अधिक फंड की घोषणा हुई, जिससे की अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से राहत दी जाए, इसका ध्यान रखा गया है। 12 जुलाई, 2023 को केंद्रीय सरकार ने 7,532 करोड़ रुपये की घोषणा एसडीआरएफ के लिए की और उसको रिलीज किया, जिससे अगर ऐसी आपदा आए, तो प्रदेश त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों का बचाव कर सके। इसमें केरल के लिए भी एक बड़ी राशि की घोषणा की गई है। यहां तक कि 15वें वित्त आयोग ने भी यह कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक पैसा चाहिए, इसलिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 1 लाख, 28 हज़ार करोड़ रुपये केंद्र सरकार sanction करेगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार से बचाया जा सके।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की घोषणा की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में एनडीएमए को बनाने का काम किया है। इसका उद्देश्य है कि चाहे केंद्र की एजेन्सीज़ हों या प्रदेश की एजेन्सीज़ हों, सारी एजेन्सीज़ का एकीकरण करके, एक साथ मिलकर ऐसे समय में कैसे करें। इसी के साथ-साथ 13 जून, 2023 को राज्य और यूटी के आपदा प्रबंधन की हमारे गृह मंत्री जी ने बैठक की। ...(**समय की घंटी**)... इसमें 8 हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके साथ-साथ माननीय प्रधान मंत्री जी और केंद्र सरकार की ओर से ऐसी अनेकों घोषणाएं की गई हैं, ताकि ऐसी स्थिति से निपटा जाए। यही मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Next, Dr. John Brittas. You have three minutes. But, I give you five minutes. Go ahead!

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I express my profound gratitude for allowing this Calling Attention Motion. With profound grief, I am participating in this discussion. Given the magnitude of the disaster, which Wayanad has witnessed, it is necessary to declare this tragedy as a 'national disaster'.

Sir, the other day, I listened to the response of the hon. Minister. And, the response is that there is no provision to declare it as a 'national disaster'. I would plead with the hon. Home Minister to please understand the extent of this tragedy. It is the worst landslide that has occurred in Kerala. The Kerala Government, with the cooperation of the agencies of the Union Government, is doing everything possible to give relief to the people. As you would appreciate, there are three stages — rescue, relief, and rehabilitation. Now, the focus is on 'rescue'. The death toll has gone up

to 157. And, we fear more deaths. There are many people who have gone missing. I would submit that some of the dead bodies were found in neighbouring district. So, the radius of this tragedy is huge. So, we have to deploy all sorts of devices to ensure that the rescue operation has got a magnitude of covering areas, which are beyond this district. Sir, we have been pleading with the Government of India to provide relief to the State of Kerala. For the information of the House, during the last seven years, 3,782 landslides occurred in the country. And, out of that, 2,239 were in Kerala alone.

About 60 per cent of the landslides happened in Kerala. That is why, when I was participating in the Budget discussion, I had expressed my reservation to the propositions of the Finance Minister when she mentioned only a few names of the States. I would urge upon the hon. Home Minister to see that there is ample assistance provided at this need of hour. We have opened up 45 relief camps in Wayanad. There are around 4,000 people in the camps. Various agencies, I would say, the people, cutting across all the political affiliations, are extending their support to give relief to the people. Two temporary hospitals have been set up in Wayanad alone. Forces including fire force, the NDRF and police are working together in tandem. I would also compliment and also express my gratitude to the Central Government for providing the help of the Army, the Navy and the Air Force, which are being utilized for these rescue operations. About 163 people have been officially declared as dead. But, as I told you in the beginning, we feel that the number will go up. Almost 250 people are still missing. It is very difficult to take out the bodies because of the debris that has heaped on these places. Sir, I have a request to you. Last time, in 2018, we had a flood, very bad flood, the worst flood in this Century. At that time, the Union Government had provided relief but even for the relief, the Union Government had charged Kerala State the money which was spent by the Air Force and also the money which was provided for rice, were demanded from Kerala Government. I would urge upon the hon. Home Minister that such things should not happen. Please consider this is the disaster of this nation. Please extend your helping hand.

MR. CHAIRMAN: Thank you, hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS: Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: I now call upon the Members whose names have been received for seeking their intervention. Members may restrict their speech to three minutes each

while raising the situation. Now, Shrimati Jebi Mather Hisham, you have three minutes.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the catastrophic Wayanad landslide. As I stepped into the Parliament now, I received a phone call. All I could hear was the cries and screams and the tears of Shobhna Soman. She lost her mother, her brother, Sudevan, brother's wife and their two children. Five members from one family, the home and the hopes and everything has swept away. The magnitude of this catastrophe is again, I reiterate, beyond measurable. I implore the Government to declare this as a national disaster. Why do I say so? That is because this is something which has affected the villages, the bridges, the roads, the houses and the families. They have to start their lives from zero. Earlier, we have had instances where Sikkim earthquake and Ladakh floods have all been under national disaster. Also, we have to have a mapping of that. It is also important that we prevent such instances from happening by having early warning system, early alerting system and mapping of such areas. The compensation of Rupees two lakhs, which has been provided, is very less. We should provide a compensation of Rs. 25 lakhs. I appreciate all the efforts of the Army, the Navy, the Air Force and all other authorities who are working there tirelessly, doing everything possible, whatever it takes, to bring back Wayanad to normalcy and save people. But, it is also important to say: Do we have a warning system? Do we have an alert system? Do we have a system of coordinated efforts? The fact is, we do not have a warning system. We are living in the age of NASA — the IPCC Report — we are living in the age of Artificial Intelligence, but when such heavy rains happen, the mud becomes weak. Do we have a system? The Opposition, one-and-a-half years ago, brought a Resolution in Kerala Assembly demanding all this. But, unfortunately, we have not learnt from the Ockhi, we have not learnt from Tsunami and we have not learnt from floods.

The fact is, we have to have coordinated efforts to have alarm system, the warning signals and coordinated efforts of all Departments. ...*(Time-bell rings)*... But from the bottom of my heart, I again say, please declare this as a national disaster and provide adequate compensation to the families who have lost everything. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri Raghav Chadha; three minutes.

SHRI RAGHAV CHADHA (Punjab): Sir, I stand before you today with a heavy heart to mourn the tragic loss of lives due to the catastrophic landslide in Wayanad. Yesterday, nature unleashed its fury, and, in an instant, several families were torn apart. The serene hills of Wayanad which once brought joy and peace now echo with the cries of those who have lost their loved ones. To the people of Wayanad, I, on behalf of my party, offer our deepest condolences. Your pain is immeasurable and your loss is shared by every citizen of this nation. As we grapple with the enormity of this disaster, let us stand in unwavering solidarity with the affected families. Let us assure them that they are not alone in this grief and we are with them and we will support them through this darkest hour.

Sir, it is imperative that we respond to this disaster with the urgency and the compassion it demands. I call the attention of the hon. Minister towards the desperate need to allocate an appropriate relief package to the State of Kerala. This package should not only provide immediate financial assistance to the affected families but also support the long-term rehabilitation and reconstruction efforts. We must ensure that the survivors have access to safe housing, medical care and psychological support to help them rebuild their lives.

Sir, I also seek the attention of the Government towards some suggestions to prepare ourselves for such unfortunate incidents in the future. First, strengthen early warning systems; second, improve infrastructure resilience; third, conduct community training; fourth, enhance inter-agency coordination; and fifth, provide comprehensive rehabilitation.

Sir, I feel that this is certainly not the time for political differences or regional biases. This is a moment for unity, for coming together as one nation to protect and support our citizens. We owe it to those who have perished and to those who have lost their homes and loved ones to create a system that minimizes the impact of such disasters in future.

And lastly, Sir, let us honour the memory of those who lost in Wayanad by committing ourselves to building a safer and a more resilient India. Let their sacrifice not go in vain and let it be a catalyst for change. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Sir, I first wish to thank you for constructively taking the suggestion of the Opposition and allowing this Calling Attention Motion. This week we have had one Calling Attention, we have had one Short Duration

Discussion and I fervently hope that this positive trend continues in the weeks to come.

Sir, first, I would like to start by paying my condolences to the families of all those who have been affected by this horrible disaster in Wayanad and prayers for the ones who are still trapped, who are still being rescued. I also wish to extend my prayers to our brave security forces who are working in extremely difficult conditions and trying to save lives.

Sir, I have three very specific questions for the hon. Home Minister to respond to in the context of this horrendous natural disaster which has happened in Kerala, which we have also seen happening in other States in the past. Sir, for the State Disaster Relief Fund, the SDRF, the quota of allocation is that 25 per cent of the funds are contributed by the State Government. However, unfortunately, the State Government has discretion on spending only 10 per cent of those funds if the Ministry of Home Affairs has not declared it as a natural disaster.

Sir, my specific question is: Will the Government consider and approve a proposal for allowing States, at least, 25 per cent of discretion on the SDRF funds? They are contributing 25 per cent. It is the money of the people of the State. Can the State use it for the State itself? That should be allowed. That is question number one. Question No. 2, in this Union Budget, we saw the Finance Minister talk about five States in terms of flood relief. West Bengal, my State, was very specifically excluded from that despite the fact that we have had devastating floods in West Bengal. But nothing was given to West Bengal. Sir, this disaster has now happened in Kerala which, as a lot of hon. Members have said before me, should be considered a natural disaster. Since the Union Budget is still under consideration right now, my specific question is: Will the Union Government, at least, now think about adding West Bengal and Kerala to the list of States that should be getting flood relief?

My third point is that in the last several years we have stopped seeing the Prime Minister doing aerial surveys. He used to do that once upon a time. He doesn't do it anymore, be it Assam, Bengal or Kerala. When the Prime Minister does an aerial survey, it sends a lot of confidence to the people and it makes them feel that they are being cared about. Will the Prime Minister, at least, now stop posing for happy photos and actually come out and go to the disaster area and do an aerial survey there in Kerala?

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) : सर, कल वायनाड में जो घटना घटी, उसमें जिन लोगों की जानें गईं, उनके लिए हम सब दिल से दुखी हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उसमें हमारे ओडिशा के दो डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं, जिनको ढूंढ़ा जा रहा है। ओडिशा में हर वक्त डिजास्टर होता

है, तूफान आता है, बाढ़ आती है। ओडिशा में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके बारे में तत्कालीन मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने जो प्लान एंड प्रोग्राम्स शुरू किए थे, वे लॉंग टर्म प्रोग्राम्स थे। इसी के कारण, ओडिशा में जान और माल की बहुत रक्षा होती थी। अगर केंद्र सरकार भी उसको फॉलो करती कि नवीन पटनायक जी ने किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज किया था, तो मैं सोचता हूँ कि उससे बहुत से लोगों की जानें बचने की उम्मीद बढ़ जाती।

महोदय, ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। आज यह केरल में हुआ, लेकिन असम और उत्तराखंड जैसे हमारे अलग-अलग राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। वहां बारिश की वजह से मिट्टी धंसने की घटनाएं हो रही हैं। उसके बारे में एक फिल्म भी बनी थी कि कैसे पानी आ गया और उसमें बहुत से लोग बह गए। इसके बारे में केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। मान्यवर, आज होम मिनिस्टर जी यहां मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, क्योंकि वहां 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसी घटनाएं जो बार-बार घट रही हैं, इनको कैसे रोका जाए, उसके लिए मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि स्पेशियली इसके बारे में कितने फंड की व्यवस्था की गई है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से कुछ स्पेशल फंड की व्यवस्था करनी भी चाहिए। भले ही कोई भी राज्य में घटना क्यों न घटे, केंद्र सरकार को ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, मैं यह उम्मीद करूंगा। सर, आज केरल में हुआ, कल असम में होगा, परसों उत्तराखंड में होगा, कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी। ...(**समय की घंटी**)...

अतः मैं केंद्र सरकार से फिर से गुजारिश करूंगा कि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएँ और फंड की व्यवस्था जरूर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, we are at loss of words to express our grief. Everyone in this world plans to live long, but such things happen suddenly and takes away the precious lives of human beings. They might have had too many responsibilities; they might have had dreams but all could have shattered and sunk in the soil. I thank you for admitting this Calling Attention. What should be done in future is the question now before us. Some said that it was a cloud burst, but the Kerala Meteorological Department has said that it is not so. Whenever we come across organisations who are indulged in maintaining global warming, I have been repeatedly telling them in many of our meetings to tackle and combat global warming. Afforestation is one of the things but, before that, deforestation should be stopped.

The main reason for landslides and such flash floods is deforestation. Many areas are suffering. Those hill stations, which used to attract us because of their greenery, now appear tonsured. This should not happen. We came to know that one environment scientist, Mr. Madhav Gadgil, had given a warning a few months before to take precautionary measures expecting that such things might happen in the very near future. Anybody cannot say these things. Only those who have very

good research can predict these, and they give very good suggestions also, but they are all ignored as if they are nobody. So, I would urge the Government to take note of all these things. Scientists and so many people have advised on how to address the issue of global warming. We come across many such suggestions, but how far are these implemented? Only the Government can do this. Had Mr. Madhav Gadgil's suggestion been taken seriously, this tragedy could have been avoided.

So, I would urge the Government again to avoid such happenings in future, like flash floods or cloudbursts. Even then, these can occur because it is part of the nature, but we have to take some precautionary measures. Deforestation should be stopped at any cost, and, at the same time, release the disaster relief funds at the right time and to the needed level of those people and the State Governments. Thank you, Sir.

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Thank you, hon. Chairman, Sir, for having this Calling Attention on this issue. Last time we heard that the death toll has arisen to 163. Dr. John Brittas told me about this. First of all, our condolences to those families who have lost their near and dear ones, as also our all kind of solidarity to the Central Government and the State Government. Everybody is vulnerable in such disasters. But, the people and communities on the margins are more vulnerable than others. In this case, if you look at the locale, they are the locale occupied by vulnerable people and communities. I think that should be first priority. With so much of technology at our command, can we broadbase our disaster preparedness, disaster prevention, disaster signals and disaster mitigation? I come from a State which is prone to such disasters, whether it is flood or even landslides in some areas. Finally, I would reiterate that such massive tragedies must unite us. It should not be seen through the prism of who is governing Kerala and who is governing Delhi. Thank you very much, Sir.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, the Wayanad District of Kerala has suffered devastating landslide which has wiped out villages and habitations. The very painful incident has happened and there is massive destruction and many people have lost their lives. The exact number of deaths is not yet known. This is not a time to score political points. This is the time for rescue and rehabilitation. So, together, we should work for rehabilitation and rescue activities. The Government of Kerala is trying to co-ordinate with all the agencies for rescue and rehabilitation. I have some reservations about the statement of one of the Members in this House, which was, I think, for scoring political gain. The entire nation should work together. If a person,

or a political party, is trying to make some political gain in such a situation, that means they don't have any idea of politics of humanity.

This disaster has caused huge loss to the economy of the State and there is a need to give special assistance to the State Government. Wayanad District in Kerala State needs huge support from the Union Government. So, the Union Government should provide a special package to the State Government. The affected people of Wayanad District are requesting for help from the entire nation. The landslide in Mundakkai village, Chooralmala and other areas is one of the biggest calamities in the State of Kerala. So, I request the Government that it should be declared as a national calamity and my humble request to the Union Government is to take a special step to address this kind of climate change.

It is the climate change which is resulting in increase in landslides and other calamities. Sir, your intervention is also very necessary in this matter. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Iranna Kadadi.

SHRI IRANNA KADADI (Karnataka): *"Mr. Chairman Sir, due to the devastating landslide incident in the Wayanad region of Kerala, hundreds of people have lost their lives. I express my deepest condolences and I sympathize with the bereaved families who have lost their near and dear ones.

Sir, due to heavy rainfall in the Western Ghats region, some parts of Karnataka have also been grappling with a similar situation. In Karnataka, five people have lost their lives. I would like to express my deepest condolences. Due to the record high rainfall, the rivers Krishna and Ghataprabha are flowing with 3 lakh cusecs of excess water. As a result, 232 villages have been inundated and 44 bridges have been submerged, resulting in severely damaged transport and communication facilities. Sir, more than 800 families have been affected and more than 4000 affected people are taking shelter in the rehabilitation facilities. Hundreds of cattle are also dead. More than 46,700 hectares of agricultural land has been submerged and the crops have been destroyed; roads and bridges have been damaged. Due to the inundation caused by the rivers, crocodiles, snakes, fish and other aquatic creatures have swum out and have entered the villages. People are frightened there. Drinking water has been contaminated due to the floods, causing its acute shortage. Sir, there is a possibility of widespread water-borne diseases among the people after the flood water recedes. There is a looming possibility of many other related calamities as well.

* English translation of the original speech delivered in Kannada.

The difficulties and hardships faced by the people living in the river basin have been a common affair every year during the monsoon season. However, the Karnataka Government has opened only a few porridge centers. The State Government is shirking off its responsibilities. So, I would like to draw your kind attention to this problem of natural calamities being faced by the people of Karnataka, and request the Central Government to help the people of Karnataka by taking appropriate measures under the National Disaster Management Authority."

MR. CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim.

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, first of all, I would request the hon. Home Minister to declare this incident as a national disaster. Sir, so many friends of mine have spoken here regarding the forecasting system with regard to the calamities. It is said, prevention is better than cure. I would like to bring forward an important point in this august House. Sir, Kerala does not have a properly functioning advanced radar-based weather forecasting system.

Sir, cyclone Ockhi hit us in 2017. There were floods in 2019. Comrade Dr. Brittas has already mentioned it here. Kerala has been demanding a modern Doppler Radar since 2013. What is the position there? In Kochi, there is radar system but it is not properly functioning most of the times and it is an old system which does not provide data in digital format to be used for decision making and the support system. The radar at Thiruvananthapuram is under ISRO and cannot be used all the time for this purpose.

In northern Kerala -- Wayanad is a part of the northern Kerala -- I would like to say here that there is not even a single radar in northern Kerala. Sir, Kerala has been demanding modern Doppler radars since 2013. I would like to bring to your attention that I raised this matter in this august House as a Special Mention, but unfortunately, the Union Government has neglected that. Sir, please listen to us. *(Time-bell rings.)* Prevention is better than cure. Kindly ensure that a proper weather forecasting system is placed in Kerala without further delay. This is my prayer.

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह नागर।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण जो दुखद हादसा हुआ, उसमें मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घटना के बाद इस देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार राज्य के मुख्य मंत्री जी से बात की और देश के गृह

मंत्री लगातार राज्य सरकार के सम्पर्क में रहकर, जो भी केन्द्र से सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है, वह लगातार सम्पर्क में रहकर, वह सहायता केन्द्र सरकार उपलब्ध करा रही है।

माननीय सभापति जी, इसी सदन में अभी कहा गया कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर लैंड स्लाइडिंग की घटनाएं हुई हैं, तो 50 परसेंट से ज्यादा केरल में हुई हैं। अगर केरल में इतनी घटनाएं हुई हैं, तो उसके बारे में क्या राज्य सरकार ने इस तरह की घटनाएं न हों, उसके बारे में कुछ सोचा, कुछ विचार किया कि आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी घटनाएं केरल में हो रही हैं, क्यों वायनाड में ऐसी घटनाएं हुईं? इसका एक बड़ा कारण है, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसका एक बड़ा कारण और है, जहां अति बारिश इसका कारण है। इसके साथ-साथ अभी हमारे माननीय सदस्य तिरुची शिवा जी ने कहा कि deforesting एक बड़ा कारण है, लेकिन वहां पर जो अवैध कब्जे और अतिक्रमण उस क्षेत्र में हुआ है, अगर उस पर समय से कार्रवाई की जाती, अगर राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करती, तो इस घटना से बचा जा सकता था। अभी हमारे एक साथी ने ...(**व्यवधान**)... मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: John, please. ...(Interruptions)... Let us converge on something positive.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: मैं उसी पर आ रहा हूं कि इतनी जानों को बचाया जा सकता था। इसके साथ-साथ अभी हमारे एक साथी ने रडार और अन्य चीजों के बारे में बात कही। सभापति जी, देश में एक व्यवस्था है। हर लोक सभा क्षेत्र से सांसद चुना जाता है। पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि रहीम साहब ने घटना पुरानी बताई। 5 वर्षों तक लगातार वायनाड ने भी अपना सांसद चुनकर भेजा। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, ये क्या कह रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I allowed everyone to say. ...(Interruptions)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. *...(Interruptions)...*

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: I am not naming anyone.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Hon. Members, suggestions have been made from every side. The hon. Member, Shri Rahim, made very important suggestions. All these suggestions are indicative so that such kind of situations do

not arise. So, if the hon. Member is saying something, he is entitled to say so. Please go ahead.

SHRI JAIRAM RAMESH: He is making a political statement, Sir.

MR. CHAIRMAN: Sir, again you are sitting and talking. Sorry, I take serious note of it. Please, hon. Member, go ahead.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सभापति जी, सांसद होने के नाते, जो वायनाड के सांसद रहे, हालांकि उन्होंने ...(**व्यवधान**)... जब वायनाड की जनता को ...(**व्यवधान**)...

SHRI JAIRAM RAMESH: *

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: *

MR. CHAIRMAN: Will you take your seat? Nothing will go on record. Hon. Member, continue.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: बेहतर होता कि उन 5 वर्षों में सांसद रहते हुए, जो वायनाड की कमियां थीं - लेकिन पूरे देश में तो उन्होंने घूम-घूमकर अन्य बातें कहीं - लेकिन वायनाड की जनता की जो समस्याएं थीं, उनको सदन में उठाने का काम वे करते, प्रधान मंत्री जी से मिलते, तो इन 143 जानों को बचाया जा सकता था। ...(**व्यवधान**)... दुर्भाग्य देखिए, वायनाड की जनता ने बहुत विश्वास के साथ एक सांसद को चुनकर भेजा कि वह हमारे सुख और दुख में, जब कोई घटना होगी, वह हमारे साथ खड़ा होगा। वहाँ से इस्तीफा देकर भागने का तो काम किया, लेकिन आज इस दुखद समय में, घटना के तीन दिन होने के बाद भी उन्होंने वायनाड की जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। महोदय, वे आज तक भी वहाँ नहीं गए हैं। आज वे दूसरे विषयों में तो इंटेरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वायनाड की जनता के पास जाकर उनका दुख बाँटने का काम नहीं कर पा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि यह जाँच भी होनी चाहिए कि इस घटना का कारण क्या था।

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ramji. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...(*Interruptions*).. I will reflect on this. Tiruchi *ji*, I will reflect on this. ...(*Interruptions*)... The Member has started speaking. ...*(Interruptions)*... I take note of your voice. Don't bother. ...*(Interruptions)*... Yes, Shri Ramji.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं और मेरी पार्टी वायनाड में जो लैंड स्लाइडिंग हुई है और जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इसके साथ ही हम कुदरत से यह प्रार्थना भी करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मान्यवर, साइंस ने देश के अंदर हमें लैंड स्लाइडिंग का एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है। इनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर पूर्वी एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगा हुआ है और आंध्र प्रदेश का जो अरकू एरिया है, वह भी इस एरिया में पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि यह लैंड स्लाइड संवेदनशील एरिया है। हमें उसके रीज़न पर बात करनी चाहिए कि हम इस गंभीर मुद्दे पर आगे की तरफ कैसे बढ़ें, हम इसको कैसे रोकें - क्योंकि यह हर साल हो रहा है। लास्ट ईयर 22 जुलाई, 2023 में महाराष्ट्र के इशालवाड़ी में हुआ, पूरा गाँव लैंड स्लाइड में दब गया और 30 से 40 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुआ, 380 लोगों की जान चली गई। आखिर ये घटनाएं कैसे रोकी जाएं - इसको लेकर हमें गंभीर होना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सजेशन्स देना चाहता हूं कि इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो नेचुरल रीजन है और दूसरा मानवजनित रीजन है। महोदय, हम नेचुरल रीजन्स को नहीं रोक सकते हैं। हम ज्वालामुखी नहीं रोक सकते हैं, भारी बारिश नहीं रोक सकते हैं, हम इन चीजों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो चीजें मानवजनित हैं, उनको रोक सकते हैं। महोदय, हम हाई लेवल पर माइन्स का जो काम कर रहे हैं, उत्खनन का काम कर रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन में जो काम हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। आपने देखा है कि कितनी भयंकर गरमी हुई और अभी जो वायनाड में घटना हुई, उसके बारे में साइंस कह रहा है कि वहाँ पर अरब सागर के अचानक गरम हो जाने की वजह से ज्यादा भारी बारिश पड़ी। महोदय, यह जलवायु परिवर्तन है और इस घटना में क्लाइमेट चेंज ही एक बड़ा रीजन दिखाई पड़ रहा है। हमें भविष्य को लेकर इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। ..(**व्यवधान**)..मान्यवर, मैं बस खत्म कर रहा हूं। महोदय, डेवलपमेंट के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़े-बड़े जंगल काट रहे हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए हमें यह प्रावधान डालना पड़ेगा कि डेवलपमेंट के नाम पर जितने जंगल काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, उतने ही पेड़ वहाँ पर लगाने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि हम इस तरह की नैचुरल डिजास्टर से आगे लड़ सकें। महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। ..(**समय की घंटी**)..

मान्यवर, सिर्फ 20 सेकंड्स दे दीजिए। इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ 2 लाख रुपये देने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे-पूरे घर तबाह हो गए हैं, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। वहाँ पर इतने घायल लोग हैं

कि 2 लाख रुपये में तो दवा भी नहीं आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए ..(**व्यवधान**)... कम से कम 25 से 50 लाख तक की राशि की जाए। महोदय, आपने यहाँ मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लहर सिंह सिरोया (कर्णाटक) **:** सभापति जी, आपने मुझे इस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल से हम बहुत दुखी हैं। चूँकि केरल हमारा पड़ोसी राज्य है, तो मैं कर्नाटक की जनता की तरफ से भी उन परिवारों के प्रति, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जैसे ही कल हमें समाचार पत्रों से मालूम पड़ा, तब तक वहाँ पर राहत की व्यवस्था पहुंच चुकी थी और राहत कार्य प्रारंभ हो चुके थे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।

सभापति जी, मैं मानता हूँ कि यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन साथ-ही-साथ यह मानवकृत भी है। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि Gadgil की रिपोर्ट की अवेहलना की गई, उसे लागू नहीं किया गया। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि यह बहुत सेंसिटिव जोन है। उस सेंसिटिव जोन में सिर्फ चाय बगान ही थे। वहाँ पर रिज़ॉर्ट बने, कई फॉल्स लेक बनीं और इस तरह से वहाँ पर पहाड़ों की कटाई हुई। मैं समझता हूँ कि पहाड़ों की कटाई करना, नदियों के रास्तों का अवरोध करना, यह बहुत बड़ा कारण रहा है। मैं इसमें किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन वहाँ जो सरकारें रहीं, उन्होंने लगातार इस बात की अवेहलना की है और वहाँ सुनियोजित काम नहीं हुए हैं। वहाँ जो विकास कार्य हुए, वे इस तरह से हुए कि वहाँ पर्यावरण का बड़ा नुकसान हुआ। ...(**समय की घंटी**)... सभापति जी, मैं भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मगर राहुल गाँधी जी ने जो पद यात्रा की थी, उस पद यात्रा में उन्होंने उन अतिक्रमणों को देखा होता, वहाँ उन पहाड़ों के साथ-साथ क्या-क्या अनर्थ हो रहा है, अगर यह भी देखा होता, तो आज यह स्थिति नहीं आती। जब हम ऐसी स्थिति में सैकड़ों भाई खो देते हैं, हम उसके बाद जागते हैं, चाहे वह जहरीली शराब के कारण हो, तो मेरा एक और निवेदन है कि कभी न कभी राज्य सभा को यह सोचना चाहिए कि समय रहते हुए, हमें इस पर कदम उठाने चाहिए और केंद्र सरकार जो योजना लागू करती है, उनका पालन करना चाहिए।

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I pay homage to all the victims who have lost their lives in this horrendous tragedy in Wayanad. My party leader, Shri Abdul Wahab, is already there in Wayanad and trying to coordinate efforts for rescue and rehabilitation. This is the monsoon season in Kerala. It has been raining in Kerala for quite some time. Now, when it rains over there, the soil gets weak. That is a natural phenomenon. But if there is a cloudburst kind of a situation -- like, 200 mm of rain happened on two consecutive days, which is, 400 mm of rain happened over there — then, the soil gets completely weak and this leads to the collapse of the mountain itself. The whole of the mountain has collapsed. Therefore, there has to be a system that pre-warns you about this particular kind of a disaster and catastrophe. I would

suggest that this particular kind of pre-warning system should be installed in the entire West Ghats, which is an ecologically fragile area. We need specialised system for these vulnerable areas. A whole task force which includes meteorological, oceanographic, geological and hydrological teams should be constituted and then this should be given to a specialised institute like Indian Institute of Technology. You should have a system comprising of all these four departments. Only then you can pre-warn this kind of cloudburst or you can pre-warn this kind of massive landslide which can happen. Landslide happened at 2 in the morning but it was not very grave but the gravest happened at 4 o'clock which shook all the villagers. Three villages are still under the debris. We do not know the number of people who are there under the debris. So, the magnitude of this is unimaginable. Secondly, this has to be treated as a national calamity, as my friends suggested over here. Thirdly, there has to be a special financial package for Kerala for this Wayanad disaster. Lastly, Kerala was excluded in the Union Budget from the Disaster Management Fund. Through this platform, I appeal to the Government to reconsider the decision. Thank you.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, a very unfortunate incident happened in Kerala. With great sorrow, all of us join with the bereaved families for their rehabilitation in future. We all know that the Prime Minister's Office has immediately sent the Minister there as a representative and the people, who lost utensils, cattle, etc. have been given immediate relief; an amount of Rs.2 lakh for the kin of the deceased and Rs.50,000 to the injured which has given a little hope. At the same time, the Home Minister and his Ministry is proactive there 24X7 with NDRF, and all other help is still going on in Wayanad region of Kerala. No doubt, it is a natural disaster; at the same time, we have to ponder over certain safeguards for this. First, proper safety measures should be taken on mountain and hilly areas.

Be it any Government, CPM is there; it may be Congress, it may be BJP or any other Government. I would only insist here that the local representatives, who have been elected by the people from the panchayat level, from the legislative level, from the Parliament level, should be more responsible to see that encroachments are not there in the hilly areas. The Government should take more concern of this so that we can save more lives in these kinds of disasters.

To conclude, I would like to say that the Central Government has given immediate assistance, help and hope to the disturbed people there. At the same time, the Central Government would be with the rehabilitation measures, with the people of Wayanad, Kerala. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Hon. Chairman, Sir, yesterday, you were kind enough to bring this to the notice of the House. You yourself voluntarily told as to what happened and what steps the Government has taken. On behalf of A.I.A.D.M.K. Party, I pay my condolences to the affected people of Wayanad. Landslides have affected most of the Wayanad District in Kerala State. Many hon. Members had requested and, yesterday also, MoS in the Ministry of Home Affairs came and gave the statement from the side of the Home Ministry about what actions the Government is taking. As you also told, the Central Government and the State Government, both are taking action. At the same time, we request to provide rehabilitation programme for the people of Wayanad immediately. Also, it has to be declared -- as other Members are also asking -- as a national disaster. A special package must also be given to the affected people in Wayanad. All Kerala MPs, like Dr. Brittas, have raised this issue. Therefore, I also join them on behalf of my Party. The Home Minister is here. All requests have been made by the Kerala MPs and we also request to see to it that a special package is given, and it is declared as a national calamity, which we are expecting. Thank you very much, Sir.

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, with a heavy heart, all of us have mourned and condoled the loss of lives in this horrible tragedy in Waynad. I associate with all my colleagues and I also wish that the Government of India and the Government of Kerala, both work hand-in-hand to help the bereaved families to resettle and start a life afresh again. It is also worth noting that the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister and also the Chief Minister of Kerala, all have been seized of this very tragic moment and have done everything possible to bring relief and succour to the people in this hour of grief. It is also important to note that the Armed Forces -- the Army, Navy, Air Force and including all other paramilitary forces -- have also joined in the rescue and relief efforts in this very difficult terrain and the conditions prevailing as of now. It is also important that many social organizations, political parties also, so also my political Party in Kerala, all are associated in whichever way they can to help the people in this hour of need. I also feel that it is a very big tragedy. Therefore, even if it is a demand that it should be a national disaster, it should be helped in that fashion. I would also like to associate that this tragedy may be considered a national tragedy. Finally, as we all now, this is not the first, but we do not want that it should ever happen again in any part of the country. Natural disasters are prone to happen, especially, in eco-sensitive zones like the entire Western Ghats also. Right from Kerala up to Maharashtra, including the Konkan region, we have the Western Ghats. We have sometimes even some such

tragedies, hopefully ever not of the scale which has happened in Wayanad, in our Konkan region also in Maharashtra.

Therefore, I would urge upon the Government and the hon. Minister--because the technologies are much better than in the past--to try to get some kind of mapping of the entire ecologically sensitive zones, especially, where there is so much heavy rainfall,--Western Ghats receive the highest rainfall probably in the country--even in the hills like Uttarakhand, Himachal Pradesh and many other parts of the country where we have heavy rains. At one time, you will have to balance the needs of humanity, growing needs of aspirational nation and the developmental needs. Everybody talks about trying to protect nature. Yes, the nature has to be protected, but we will also have to balance the needs of development and growth. For that, I think, proper approach, a humane approach and a practical approach will have to be adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the hon. Home Minister.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : सभापति महोदय, भारत सरकार का जो स्टेटमेंट है, वह नित्यानन्द राय जी ही बताएँगे, मगर मैं कुछ चीजों की स्पष्टता करने के लिए आपकी अनुमति से इस सदन के सामने खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, सरकार की ओर से जवाब नित्यानन्द राय जी ही देने वाले हैं। जब यहाँ पर एक घंटे की चर्चा अपने अनुमोदित की, तब मुझे यह लगा था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका-टिप्पणियाँ नहीं होंगी। ख़ैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियाँ भी हुईं और सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में, मुझे मालूम नहीं है, मगर माननीय महोदय, मुझे स्पष्टता करनी है, आप के माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को कि यहाँ लोग 'early warning', 'early warning' बोलते ही गए, अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द हैं, अपने भाषण में डाल कर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से early warning दे दी गई थी। 7 दिन थे, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई। मान्यवर, 26 तारीख को यह कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, landslide होने की संभावना है, mud भी rush होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दब कर मर भी सकते हैं। मान्यवर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मगर भारत सरकार के early warning system पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूँ कि "Please listen us", "Please listen us" मत चिल्लाइए, "Please read it." जो warning भेजा है, उसको पढ़िए ज़रा। इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की warning का उपयोग करके zero casualty

disaster management किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी कहना चाहता हूँ, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले cyclone का alert भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वह भी गलती से मारा गया। सर, गुजरात सरकार को हमने cyclone का alert 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जो घिसे-पिटे शब्द यहाँ लेकर आए हैं और demand ही करते जा रहे हैं, early warning system है। भारत सरकार ने 2014 के बाद early warning system के लिए 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मान्यवर, इसको साझा किया जाता है। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वह सूचना साइट पर सबके लिए उपलब्ध भी है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है।

2.00 P.M

मगर कुछ लोगों को है कि वे यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं हैं, विदेश की ही खोलते हैं। अब विदेश की साइट पर इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगा नहीं, इसके लिए तो हमारी साइट देखनी पड़ेगी।...(**व्यवधान**)... चूँकि मैंने आपको ध्यान से सुना है, इसलिए आप भी सुनिए।...(**व्यवधान**)... इस तरह से नहीं चलेगा। यह सदन है।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, please. I will not allow. Facts, figures and details are being imparted. Hon. Minister, please continue.

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं तो उसी उद्देश्य से ही कहता हूँ कि इसको सुन कर सभी राज्य अलर्ट हों, अर्ली अलर्ट हो जाए। मेरा किसी पर ताना मारने का आशय नहीं है।

अर्ली वार्निंग सिस्टम वर्षा के लिए है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहाँ तक कि बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहाँ गिरेगी, वह सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती है। मगर ये इसका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि जानकारी का अभाव होगा। अगर जानकारी का अभाव है, तो भी ठीक नहीं है और अगर राजनीति है, तो यह बहुत दुखद है।

मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और उसके परिणाम भी आए हैं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थीं कि वहाँ लैंड स्लाइड हो सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहाँ भेजीं। मान्यवर, सारे लोग मुझसे इतना पूछते हैं, लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर vulnerable situation तो थी। क्या उनको शिफ्ट किया गया है? उनको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? अगर शिफ्ट किया गया, तो मरे कैसे?...(**व्यवधान**)...

डा. जॉन ब्रिटास : शिफ्ट किया है।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह : शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है।...(**व्यवधान**)...

डा. जॉन ब्रिटास : नहीं, नहीं।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह : जितना बोलिएगा, उतना नुकसान होगा।...(**व्यवधान**)... मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर शांति से बैठ कर सुनने नहीं आया हूँ।...(**व्यवधान**)...

डा. जॉन ब्रिटास : कोई आरोप नहीं है।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Take your seat, Dr. John Brittas. Why are you interrupting? You have raised your points. Please.

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी 2014 में प्रधान मंत्री बने और 2016 से अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2023 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है, तो वह भारत में है। इसका सात दिन पहले अनुमान देने वाले चार ही देश हैं, उनमें से एक भारत भी है, मगर उसको पढ़ना पड़ता है। डिमांड करने से कुछ नहीं होता है।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि डिजास्टर के पैसे को रिलीज़ करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। वह गलत है, मान्यवर। मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूँ, क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए। एसडीआरएफ में 10 परसेंट राशि कोई भी राज्य सरकार अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकती है और 100 परसेंट राशि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के हिसाब से बिना भारत सरकार के परमिशन से खर्च कर सकती है। इसके लिए भारत सरकार की किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन को फॉलो करना है। मगर डिजास्टर का जो पैसा है, वह किसी और हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकता, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। फिर भी आप 10 प्रतिशत खर्च डिजास्टर के नाम पर कुछ भी करें, उसके लिए कोई नहीं पूछता है। आपको गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए 90 परसेंट खर्च करने के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, डिटेल्ड स्टेटमेंट नित्यानन्द जी पढ़ेंगे। मैं स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ स्पष्टता ही कर रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल के बारे में भी कहा गया। हमने 6,244 करोड़ रुपए 2014 से 2024 तक पश्चिमी बंगाल के लिए अप्रूव किया है और जिस प्रकार से खर्च का हिसाब आता है, उस हिसाब से राशि रिलीज़ की जाती है। उसमें से 4,619 करोड़ रुपए हमने reimburse कर दिया है। मगर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है हिसाब भेजने में। अब वह तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता, उसको तो पश्चिमी बंगाल सरकार को ही करना पड़ेगा। अकाउंट देना पड़ता है, क्योंकि यह सरकार है, कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है। सरकार के कुछ रूल्स, रेग्युलेशन्स होते हैं, accounting system होता है, एजी का ऑडिट होता है। हम किसी को नहीं मानेंगे, तो थोड़ी

तकलीफ आएगी। मगर धीरे-धीरे आदत पड़ रही है, इम्प्रूवमेंट आया है, इसलिए इनका 6,244 करोड़ रुपए में से 4,619 करोड़ रुपया रिलीज़ हो चुका है।

मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि early warning दी गई थी और इसीलिए 23 तारीख को हमने वहां पर एनडीआरएफ की 9 बटालियंस भेज दी थीं और 3 बटालियंस कल रवाना की हैं। अगर वे वहां एनडीआरएफ की बटालियंस उतरने से भी अलर्ट हो जाते, तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। यह समय केरल की सरकार के साथ खड़े रहने का है, केरल की जनता के साथ खड़े रहने का है और जिन लोगों की हानि हुई है, उनके साथ खड़े रहने का है।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि irrespective of party politics, नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार, दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, इसमें किसी को संशय नहीं रखना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai, may now reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कल सदन में अपने बयान में बताया था कि केरल राज्य के वायनाड जिले में कल सुबह के शुरुआती घंटों में भूस्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, उन दोनों ने तत्परता के साथ उसी समय राज्य सरकारों से संपर्क किया और केंद्र सरकार जितनी सहायता कर सकती थी, वह उन सारी सहायताओं में जुट गई।

सर, मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो नवीनतम जानकारी है, उसमें राहतकर्मियों के द्वारा अब तक 133 शवों को निकाल लिया गया है। सर, मृतकों की यह संख्या बढ़ सकती है। हमें राज्य सरकार से जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग आंकड़े देते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके आदेश से राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन जी स्थिति का जायजा लेने के लिए कल रात ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं। वहां की जो परिस्थिति थी, उसमें वहां पहुंचना दुर्लभ लग रहा था, फिर भी वे वहां पहुंचे और गृह मंत्री जी से संपर्क कर उनको लगातार वहां की स्थिति की जानकारी देते रहे। माननीय प्रधान मंत्री जी भी उनसे अपडेट लेते रहे। माननीय गृह मंत्री जी ने कल ही केरल के माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात की। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा भी उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार से हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी और की जा भी रही है। इस घटना के तुरंत बाद एनडीआरएफ, वायु सेना, भारतीय सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की टीमें वहां खोज और बचाव अभियान में जुट गईं और वहां लगातार तत्परता से काम कर रही हैं। वहां तीन बेली पुलों के निर्माण के लिए सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के columns तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ की चार टीमें, सेना के चार columns, नौसेना की एक टीम, तटरक्षक बल की तीन यूनिट्स, राज्य सरकार की अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा, पुलिस और स्थानीय Emergency

Response Team के लगभग 1,200 बचावकर्मी बचाव और राहत अभियान में 24 घंटे कार्य कर रहे हैं।

वहां खोज और बचाव अभियान के लिए dog squad को भी तैनात किया गया है। वहां सेना की DSC centre, Kannur की दो टुकड़ियाँ भी तैनात की गई हैं। Trivandrum की 91 Infantry Brigade की दो टुकड़ियों को वहां रवाना कर दिया गया है। भारतीय सेना के दो हेलीकॉप्टर्स और नौसेना के एक हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में विशेष रूप से लगे हैं। सेना की मेडिकल टीमें घायलों को चिकित्सा प्रदान कर रही हैं। वहां श्रमिक भूमि मार्ग से आवाजाही कर सकें, इसके लिए वहां मार्ग स्थापित करने एवं बचाव कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS Zamorin को क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी ओर तैनात कर दिया गया है।

आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त संसाधन भेजे जा रहे है। उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष, एक जो NDRF का आपदा प्रबंधन का और दूसरा गृह मंत्रालय का है, दोनों ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वे 24X7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। आज ही State Disaster Response Fund से 145 करोड़ रुपये की राशि वहां की राज्य सरकार को प्रदान कराई गई है। महोदय, वहां पहले ही SDRF के तहत 394 करोड़ रुपये की बैलेंस राशि - सारे विषयों पर माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जानकारी दी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले Super Cyclone आया था, उसमें करीब 10 हज़ार लोगों की मौत हुई थी, आज हम मौत के मामले में ज़ीरो की संख्या पर पहुंच गए हैं। यह प्रधान मंत्री जी के प्रेरणा नेतृत्व में disaster management के लिए किया जा रहा काम, तकनीकि का अधिक उपयोग, आपदा प्रबंधन में दी जा रही राशि और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर काम हो रहा है। पर्यावरण की बात हुई - गृह मंत्रालय ने और भारत सरकार के बहुत सारे लोंगों ने और भारत सरकार की प्रेरणा में बहुत सारी संस्थाओं ने पेड़ लगाने का काम किया है और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में पैरामिलिट्री फोर्सेज़ ने भी रिकॉर्ड स्तर पर पेड़ लगाने का काम किया है। सर, तकनीक का उपयोग बिल्कुल किया जा रहा है। अब भारत का आपदा प्रबंधन ऐसा है, जिस पर देश के साथ-साथ विदेशों को भी भरोसा है। कई देशों में आपदा के समय, चाहे वह भूकंप हो या अन्य आपदा हो, उस समय भी भारत बढ़-चढ़ कर उनके सहयोग के लिए आगे गया है। यहां इसके कई उदाहरण हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी तत्परता के साथ लगातार निगरानी रख रहे हैं। सर, कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी दिन-रात लगातार राज्यों को सहयोग भी कर रहे हैं, बचाव और राहत कार्य की निगरानी भी कर रहे हैं। जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, वैसे-वैसे केंद्र सरकार राज्य को सहायता पहुंचा रही है।

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Special Mentions. Shri Sanjay Seth.